

भारत सरकार  
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय  
औषध विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 788  
दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र

788. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कुल कितने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र (पीएमबीजेके) खोले गए हैं;
- (ख) वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों और विशेषकर महाराष्ट्र राज्य सहित राज्य-वार कितने नए पीएमबीजेके खोले जाने का प्रस्ताव है; और
- (ग) वर्ष 2023-24 में आज की तिथि तक नए पीएमबीजेके खोलने के लिए बजट आवंटन और उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग की गई धनराशि का अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों और विशेषकर महाराष्ट्र राज्य सहित राज्य-वार व्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कुल 178 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले गए हैं। इनका विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	खोले गए जेएके
1	2021-22	49

2	2022-23	36
3	2023-24	93
	<b>कुल</b>	<b>178</b>

महाराष्ट्र राज्य में, इस योजना की शुरुआत से लेकर दिनांक 31.10.2024 तक, राज्य के सभी 36 जिलों और 180 ब्लॉकों को कवर करते हुए कुल 702 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले गए हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पीएसीएस) श्रेणी के तहत, महाराष्ट्र में 52 जेएके भी खोले गए हैं।

(ख): सरकार ने मार्च 2025 तक देश भर में 15,000 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोलने का निर्णय किया है। नए जेएके खोलने के लिए कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और क्षेत्र-विशिष्ट लक्ष्य नहीं है।

तथापि, महाराष्ट्र सहित देश के सभी जिलों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

(ग): वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	आबंटित निधि (रुपए करोड़ में)	उपयोग की गई निधि (रुपए करोड़ में)
1.	2023-24	110.00	110.00

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और क्षेत्र-विशिष्ट बजट आवंटन नहीं किया गया है।

\*\*\*\*\*